

मुख्य सचिव ने एम-पासपोर्ट ऐप लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव नरिजन आर्य ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तथा राज्य के गृह विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एम-पासपोर्ट ऐप का शुभारंभ किया। प्रदेश के सभी पुलिस थानों को ऐप से जोड़कर मैपिंग कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने एम-पासपोर्ट ऐप के बारे में बताया कि विदेश मंत्रालय तथा गृह विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जारी इस ऐप में पुलिस सत्यापन के लिये अधिकतर सवालों का जवाब 'हाँ' या 'नहीं' में रिकॉर्ड किया जाता है।
- यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुवर्धनकारी है। इसके शुरू होने से पासपोर्ट के लिये पुलिस सत्यापन की अवधि दो सप्ताह से घटकर एक सप्ताह हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुछ जगहों पर 'पायलट रन' के बाद अब इसे पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है।
- विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में एम-पासपोर्ट ऐप के उपयोग से भारतीय नागरिकों के लिये पासपोर्ट प्राप्त करना तो आसान होगा ही, विदेश में रह रहे भारतीयों तथा भारतीय मूल के लोगों के लिये 'पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट' प्राप्त करने में भी यह ऐप उपयोगी होगा।
- पुलिस महानिदेशक इंटेल्जिंस उमेश मशिरा ने बताया कि पुलिस सत्यापन में लगने वाले समय को कम करने के लिये कॉन्स्टेबल स्तर तक पुलिसकर्मियों का क्षमता संवर्धन किया जा रहा है। इस सुवर्धन से पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में पुलिस की सेवा गुणवत्ता में सुधार आएगा।